भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1205

दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

भू-स्थैतिक मानचित्रण

1205. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भू-स्थैतिक मानचित्रण और अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके भूमि खंडों की पहचान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कोई उपाय कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी प्रौद्योगिकी का उपयोग दिल्ली के गांवों में भी किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) सरकार ने **डीआईएलआरएमपी** के तहत उन्नत भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों और अन्य प्रौद्योगिकियों जैसे **एरियल मैपिंग, हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन/डिफरेन्शियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (ईटीएस/डीजीपीएस) आदि** का उपयोग करते हुए भूमि खंडों/पार्सलों की पहचान की प्रक्रिया को आसान और बेहतर बनाने हेतु कई उपाय किए हैं। तथापि, **जियो-स्टेशनरी मैपिंग** का उपयोग इसके मध्यम स्थानिक रिजोल्यूशन के कारण सीधे तौर पर नहीं किया जाता है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमि अभिलेखों में सटीकता और पारदर्शिता में वृद्धि के लिए अपनी आवश्यकतानुसार **जीआईएस आधारित प्लेटफॉर्म** का भी उपयोग किया जाता है। डीआईएलआरएमपी में सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण के लिए निम्नलिखित तीन कार्य पद्धतियां विहित की गई हैं;

I. ईलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ईटीएस)+ डिफ्रेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस)
II. हाइब्रिड एरियल फोटोग्राफ्स+ईटीएस+डीजीपीएस
III. हाइब्रिड हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी+ईटीएस+डीजीपीएस (<1 एम स्पेशियल रिजोल्यूशन)

(ख) जी, नहीं।

******